यूपी में छोटे कोल्ड चेन स्टोरेज पर जोर देगा केंद्र

नेशनल कोल्ड चेन समिट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दी जानकारी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। केंद्र सरकार अभी तक 50 एकड़ या उससे अधिक भूमि होने पर उद्यमियों और एग्रो-बिजनेस से जुड़े लोगों को कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने के लिए सब्सिडी दे रही है, लेकिन अब छोटे कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने जोर देते हुए भूमि सीमा घटाकर 10 से 15 एकड़ की जा रही है।

राजधानी में शुक्रवार को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) की राष्ट्रीय कोल्ड चेन स्टोरेज समिट में राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में केंद्र ने देश में छह कोल्ड चेन स्टोरेज स्थापित किए हैं, जिनमें तीन आगरा, औरैया और शाहजहांपुर में हैं। इसके बाद, अब छोटे कोल्ड स्टोरेज चेन स्थापित करने को प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश को पूरी सहायता देने के लिए केंद्र तैयार है। नाबार्ड जैसे संस्थान को इस पर जोर देना चाहिए।

साध्वी ने कहा कि विश्व की तुलना में फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज के क्षेत्र में देश अभी बहुत पीछे है। कोल्ड स्टोरेज के लिए मैदानी क्षेत्रों में केंद्र सरकार 25 फीसदी और पहाड़ी इलाकों में 75 फीसदी तक सब्सिडी देती है। इस मौके पर आईसीसी के महानिदेशक डॉ. राजीव सिंह ने समिट के विभिन्न बिंदुओं का महत्व बताया। कार्यक्रम में आईसीसी के क्षेत्रीय पदाधिकारी, नाबार्ड लखनऊ के सीजीएम एके पांडा, एसबीआई के डीजीएम कुलदीप कुमार गंजू, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त दुग्ध आयुक्त कृष्ण कुमार गुप्ता आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे।

लखनऊ में आयोजित नेशनल कोल्ड चेन समिट में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति व सूबे के मंत्री मूलचंद चौहान।

यूपी में फल सब्जियों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने का लक्ष्य

प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री मूलचंद चौहान ने बताया कि 2012 में खाद्य प्रसंस्करण नीति लाकर सूबे की सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। फल सब्जियों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसी क्रम में आगरा-लखनऊ-बलिया में हाईवे के किनारे मंडियां बनाई जा रही हैं।

134 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 9 यूपी में

कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की संयुक्त सचिव अनुराधा प्रसाद ने बताया कि 2008 से भारत सरकार कोल्ड चेन स्टोरेज को बढ़ावा दे रही है। इस दौरान देश में 134 प्रोजेक्ट शुरू हुए, जिनमें से सिर्फ नौ ही यूपी में शुरू हुए हैं।